निधि ...at al(April 2023). इनेलो भाजपा गठबन्धन सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य
International Journal of Economic Perspectives,*17*(04) 300-306
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

इनेलो–भाजपा गठबन्धन सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

निधि
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान व लोकप्रशासन विभाग,
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,
अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)

प्रो० (डॉ०) सी० बी० सैनी
शोध–निर्देशक
राजनीति विज्ञान व लोकप्रशासन विभाग,
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,
अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)

सार

हरियाणा में 'इनेलों भाजपा' गठबन्धन सरकार ने समाज कल्याण के कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता दी तथा जनकल्याण की जितनी अधिक योजनाएं और कार्य इस गठबन्धन सरकार ने किये, उतने किसी अन्य सरकार द्वारा कभी नहो किये गये। यह सरकार अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा उत्थान के लिए वचनबद्ध थी। इस सरकार का उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना था, जहाँ ऊँच–नीच और भेद–भाव की कोई दीवार न हो। इस सरकार ने समाज कल्याण कार्यो के लिए सबसे पहले बुढापा पैंशन, विधवा पैशन, तथा विकलांग पैशन 100 रूपये से बढाकर 200 रूपये प्रतिमास कर दी। बुढ़ापा पैशन की पात्रता के लिए भूमिसीमा और आय सीमा की शर्त हटा दी गई तथा केवल सम्पन्न व्यक्तियों को इस दायरे से बहार रखा गया। यह गठबन्धन सरकार अस्वस्च्छ व्यवसायों में लगे लोगों के पुनर्वास हेतु तथा उन्हें आजीविका का वैकल्पिक साधन उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत रही।

की–वर्ड :– कल्याण, पैंशन, रूपये

भूमिका

हरियाणा में 'इनेलों भाजपा' गठबन्धन सरकार ने समाज कल्याण के कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता दी तथा जनकल्याण की जितनी अधिक योजनाएं और कार्य इस गठबन्धन सरकार ने किये, उतने किसी अन्य सरकार द्वारा कभी नही किये गये। यह सरकार अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा उत्थान के लिए वचनबद्ध थी। इस सरकार का उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना था, जहाँ ऊँच–नीच और भेद–भाव की कोई दीवार न हो। इस सरकार ने समाज कल्याण कार्यो के लिए सबसे पहले बुढापा पैंशन, विधवा पैशन, तथा विकलांग पैशन 100 रूपये से बढाकर 200 रूपये प्रतिमास कर दी। बुढ़ापा पैशन की पात्रता के लिए भूमिसीमा और आय सीमा की शर्त हटा दी गई तथा केवल सम्पन्न व्यक्तियों को इस दायरे से बहार रखा गया। इस सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग 7 लाख नए वृद्धों को इसमें शामिल किया गया। इस सरकार द्वारा हर महीने औसतन 25 करोड़ रूपये वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को पैशन के रूप में दिये गये। अपने चार वर्षो के कार्यकाल के दौरान इस सरकार द्वारा इन तीनों वर्गो के लगभग 13.15 लाख लाभनुभोगियों को 1208 करोड़ रूपये की धनराशि पैशन के रूप में दी गई। शिक्षित विकलांग बेरोजगारों को जिनके नाम बेरोजगार कार्यालया में दर्ज थे, उनकी योग्यता अनुसार दिये जाने वाले बेरोजगारी भत्ते में 50 रूपये प्रतिमास की बढ़ोतरी की गई। साठ साल से अधिक बुजुर्गो को मुफ्त चिकित्सा सुविधा व ऐनके दी

© 2023 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: निधि
Submitted: 27JFeb 2023, Revised: 09 March 2023, Accepted: 18 March 2023, Published: April 2023

गई तथा इनकी सहायता के लिए हर गाँव में वृद्ध विश्राम गृह बनवाने की घोषणा की तथा इस सरकार के कार्यकाल के दौरान ताऊ देवीलालवृद्ध विश्राम गृहों को निर्माण कार्य पूरा हो गया तथा तथा 202 केन्द्र निर्माण धीने थे। इसमें लगभग 13 करोड रूपये खर्च हुए। अनुसूचित जाति, विमुक्त एवं टपरीवास जाति की लडकियों की शादी पर 5100 रूपये का 'कन्यादान' देने की अनुठी योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 19000 लाभपात्रों को 9 करोड 73 लाख रूपये की धनराशि वितरित की गई। औद्योगिक श्रमिकों की लडकियों की शादी पर भी 5100 रूपये 'कन्यादान' दिया गया।[1]

यह गठबन्धन सरकार अस्वस्च्छ व्यवसायों में लगे लोगों के पुनर्वास हेतु तथा उन्हें आजीविका का वैकल्पिक साधन उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत रही। इन वर्गों के लोगों को बढ़ई का काम, किरयाने की दुकान, ब्यूटीपार्लर, टी.वी. मरम्मत, ट्रैक्टर मरम्मत, साईकिलों की मरम्मत, वैल्डिंग, ऑटोरिपेयर, आटा चक्की, बैंड बाजा, झोटा – बुग्गी खरीदने व फोटोग्राफी, डैटिंग, पेटिंग आदि व्यवसायों के लिए ऋण सबसिडी व मार्जिन मनी उपलब्ध करवाई गई। इन व्यावसायों में इन वर्गों के लोगों को 6 महीने तक प्रशिक्षण भी दिलवाया गया। तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थी को 500 रूपये प्रतिमास की दर से वजीफा भी दिया गया। अनुसूचि जातियों एवं पिछड़े वर्गों के 47,481 लोगों को स्वरोजगार के लिए 117 कराड 41 लाख रूपये से अधिक के ऋण आसान शर्तो पर उपलब्ध करवाये गये।

इस सरकार ने महिलाओं की समस्याओं के निवारण हेतू 'राज्य महिला आयोग' का गठन किया। दहेज प्रथा की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम' को प्रभावी रूप से लागू किया गया। महिलाओं के विकास के लिए राज्य सरकार ने महिला जागरूकता एवं प्रबन्धन अकादमी, राईको क्षत्रिय स्तरीय जैण्डर प्रशिक्षण संस्थान के रूप में अपग्रेड किया अनुसुचित जाति एवं विमुक्त जाति की विधवा औरतों की लडकियों की शादी पर 10000रूपये अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत 3,315 लाभ पात्रों को 331.50 लाख रूपये प्रदान किये गये। इस सरकार ने महिलाओं सशक्तिकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत 'स्वयं सिद्धा' योजना को स्वीकृत किया। जिसको लागू करने के लिए 22060 लाख रूपये की पांच वर्ष के लिए 'राज्य कार्य योजना' का अनुमोदन किया गया। इसके अन्तर्गत 839 स्वयं सहायता समूह बनाए गये। 'अपनी बेटी अपना धन' योजना के अन्तर्गत 206129 माताओं को 500 रूपये की दर से सहायता राशि दी गई। इस योजना के अन्तर्गत कुल 1277.17 लाख रूपये व्यय हुए।

इस गठबन्धन सरकार के शासन में लगभग 2 लाख लोगों को सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार दिया गया। तथा इस सरकार ने पढ़े–लिखे बेरोजगार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया। 1 नवम्बर, 2003 से स्नातक व तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को 200 रूपये प्रतिमाह तथा 10वी पास बेरोजगारों को 100 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया गया द्य इस सरकार ने नौकरी के आवेदन–पत्रों के साथ लगने वाली फिस माफ कर दी। इस सरकार के दौरान बेरोजगार युवकों को आवेदन–पत्र के साथ कोई फीस नही देनी पडती थी, जबकि पहले यह फीस 500 रूपये थी।[2]

इस सरकार के कार्यकाल में हर मेहनतकश कमेरे दिहाड़ीदार की न्यूनतम 100 रूपया प्रतिदिन की दहाड़ी निश्चित की गई। देश के किसी भी राज्य में मेहनत के पसीने का इतना मुआवजा नही मिलता था। इस सरकार के शासनकाल में प्रदेश के हर शहर में आम लोगों के सुस्ताने या इक्ट्ठा बैठनेके लिए सुन्दर पार्को का निर्माण करवाया गया। शहरी विकास के लिएहुड्डा के माध्यम से ही 1295 करोड़ रूपये खर्च किये गये। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान के लिए नये सिरे से सर्वेक्षण करवाया, ताकि उन्हें पीले कार्ड दिये जा सके।[3]

हरियाणा की 'इनेलो – भाजपा' सरकार ने राज्य में खेलों को बढावा देने के लिए नई खेल नीति तैयार की राज्य सरकार ने ओलम्पिक खेलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को क्रमशः एक करोड़, 50 लाख तथा 25 लाख रूपये की नकद राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की। इसके फलस्वरूप ओलम्पिक खेलों में भारोतोलन में कांस्य पदक प्राप्त

© 2023 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: निधि
Submitted: 27JFeb 2023, Revised: 09 March 2023, Accepted: 18 March 2023, Published: April 2023

करने वाली हरियाणा की श्रमति कर्णम मल्लेश्वरी को 25 लाख रूपये की राशि प्रदान करके मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जा रहे खिलाडियों को हरियाणा परिवहन की बसों में किराये में 75 प्रतिशत की छूट दी गई तथा राज्य के अर्जुन अवार्ड व भीम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों व ओलम्पिक खिलाड़ियों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी गई। राज्य में खिलाड़ियों का खुराक भता 30 रूपये प्रतिदिन से बढाकर 50 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया तथा सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए सरकारी बोर्डो और निगमों की नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण निश्चित किया गया द्य इस सरकार ने अपने चार वर्षो के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओ में पदक प्राप्त करने वाले 2358 खिलाड़ियों को 5 करोड 31 लाख रूपये की नकद राशि ईनाम के रूप में दी।[4]

इस सरकार ने अपने कार्यकाल में कर्मचारी वर्ग को भी अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई। प्रदेश के सभी कर्मचारियों को वो सभी सुविधाएं व वेतनदरें मिली जो केन्द्र न समय–समय पर दी। इस दौरान सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 35वर्ष से बढाकर 40 वर्ष कर दी गई।

इस गठबन्धन सरकार ने हरियाणा राज्य में कलाकारों व साहित्यकारों को भी सम्मानित किया। सरकार द्वारा सभी भाषाओं के विकास के लिए चार अलग–अलग अकादमियां बनाई गई। इस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में पहली बार, साहित्यकारों को सम्मानित करने की परम्परा चली। हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढाने में योगदान देने वाले हरियाणा के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु नतृको, संगीतकारों और अभिनेताओं का 500–500 रूपये प्रतिमास पैशन शुरू की गई1[5]

हरियाणा सरकार अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से देशभर में अग्रणी रही। 'इनेलो भाजपा' गठबन्धन सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक अनुठी चौधरी देवीलाल जनसुरक्षा बीमा योजना (देवी रक्षक) शुरू की गई। हरियाणा देश का पहला राज्य रहा, जिसने इस तरह की 'सामाजिक सुरक्षा योजना' लागू की। इस योजना के तहत 18 से 80 वर्ष की आयु वर्ग के परिवार के कमाउ सदस्य की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर तीन दिन के अन्दर मृतक के आश्रित को एक लाख रूपये की मआवजा राशि दी गई। इसी तरह से दुर्घटना में स्थायी रूप से शत–प्रतिशत अपंग होने की स्थिति में एक लाख रूपये तथा विकलांगता के आधार पर 25 हजार रूपये से लेकर 50 हजार रूपये तक की वितिय सहायतादी गई। इस सरकार ने समाज कल्याण के कार्य राज्य स्तर पर ही नही किये, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी किये। इसमें चाहे वह गुजरात में भूकम्प पीड़ित लोगों की सहायतो हो, या राजस्थान में सुखे से ग्रस्त लोगों की या चाहे उड़ीसा में से बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता हो। इस गठबन्धन सरकार ने इन राज्यों में हर प्रकार की सहायता पहुँचाई। राजस्थान मे सुखा पड़ने पर लोगों व पशुओं को भूख से मरने से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने यहां से अनाज तथा भूसा भेजा। मुख्यमंत्री औम प्रकाश चौटाला ने खुद जगह–जगह भूसे के ट्रक भरवाकर राजस्थान रवाना किए तथा रेलगाड़ियों से राशन सामग्री भेजी। हरियाणा सरकार ने 2001 में गुजरात भुकम्प त्रासदी में गुजरात के 19 गांव गोद लिये। सरकार द्वारा वहां कपडे, रोटी, पानी, कैम्बल तथा जरूरत का सभी समान उपलब्ध करवाया। हरियाणा सरकार के इस कार्य की प्रसन्न केन्द्र सरकार तथा विदेशी सरकारों ने भी की।[6]

प्रदेश में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस सरकार ने अनेक कदम उठाए। सरकार द्वारा समाज के सभी कमजोर वर्गो, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के हितों को पूर्ण सरक्षा प्रदान की गई। पुलिस बल को मजबूत करने के उद्देश्य से सिपाहियों, उप–निरीक्षको और अन्य पदों की भर्ती की गई। भारत सरकार ने हरियाणा राज्य के लिए वर्ष 2003 में द्वितीय इंडिया रिजर्व बटालियन स्वीकृत की, ताकि कानून–व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। इस सरकार के कार्यकाल में राज्य के जेल प्रशासन को सुदृढ़ किया गया। इस सरकार के चार वर्ष के शासनकाल के दौरान राज्य में कानून एव व्यवस्था के कारण स्थिति शांतिपूर्ण तथा पूरी तरह नियन्त्रण में रही। कोई भी आतंकी

© 2023 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: निधि
Submitted: 27JFeb 2023, Revised: 09 March 2023, Accepted: 18 March 2023, Published: April 2023

घटना राज्य में नही हुई तथा अपराध कास्तर भी गिरा। हरियाणा में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 105.59 करोड़ रूपये व्यय किये गये, तथा इसके अन्तर्गत तीन वर्षो के दौरान 991 वाहन खरीदे गये जिन पर 23 करोड 62 हजार 175 करोड रूपये खर्च हुए। जनता–पुलिस सम्बन्धों को सुधारने के लिए जनता पुलिस सम्मेलन, नागरिक प्रपत्र (सिटीजन चार्टर), 'घरेलू हिंसा' पर राष्ट्रीय सेमिनार, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा भ्रूण हत्या कारण व रोकथाम के सम्बन्ध में कार्यशाला, 51वे अखिल भारतीय पुलिस खेलों तथा ग्राम अपनाने की नीति इत्यादि के जागरूकता अभियानों के द्वारा जनता व पुलिस में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम करने की व्यापक कदम उठाये गये। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा 4,864 सिपाहियों की भर्ती की गई, जिनमें से 1010 सिपाही अनुसूचित जाति के थे। 4,547 सिपाहियों के पद मुख्य सिपाही तथा 879 मुख्यसिपाही के पदों को अपग्रेड करके सहायक उपनिरिक्षक बनाया गया। इस दौरान राज्य में 16 नये पुलिस स्टेशन स्थापित किये गये।[7]

हरियाणा में 'इनेला – भाजपा' गठबन्धन सरकार ने जनवरी, 2004तक अपने चार वर्षो के शासनकाल में अनेक विकासात्मक कार्य किये तथा बहुत से विकास कार्यो की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री औम प्रकाश चौटाला ने सभी 90 विधानसभा खण्डों में 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत पूर्ण विकास कार्य करवाये। लोगों की समस्याओं को स्वयं उनके पास जाकर सुना तथा उन समस्याओं का समाधान तत्काल करने की भी कोशिश की। इस गठबन्धन सरकार ने हरियाणा राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के अनेकों उपलब्धियां हासिल की तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य किया। इस सरकार ने4 वर्षो म जितने विकास कार्य किये उतने पिछले 40 वर्षो में किसी सरकार ने नही किये।

परन्तु इनेलों– भाजपा' गठबन्धन सरकार ने अपने कार्यकाल में जिन आलोचनाओं का सामना किया, उन्होंने इस गठबन्धन सरकार की सफलताओं की चमक को कम कर दिया। इस सरकार ने राज्य में कई ऐसे कार्य किए, जिन्होंने जनता के सामने इस गठबन्धन सरकार की छवि को धूमिल कर दिया। प्रत्येक विरोधी राजनैतिक दल द्वारा इसकी आलोचना की गई।

हविपा सुप्रीमों चौ. बंसीलाल ने 'इनेलो – भाजपा' गठबंधन सरकार को चौ. औम प्रकाश चौटाला की तानाशाह सरकार बताई। फतेहाबाद उपचुनाव के दौरान चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने, चौ. औमप्रकाश चौटाला तथा उनके बेटों को तानाशाह कहकर सम्बोधित किया। चौ. बंसीलाल ने आरोप लगाया की इनके शासनकाल में कानून तथा व्यवस्था ठप्प हो गई तथा दिन दहाड़े अपराध हुए। इन्होंने दलीना कांड तथा कंडेला कांड का आरोप भी चौटाला सरकार पर लगाया। चौ. बंसीलाल ने आरोप लगाया की कि "मुख्यमंत्री औमप्रकाश चौटाला द्वारा विकास कार्यो की जो उपलब्धियों ली गई, वास्तव में वे विकास कार्य उनकी सरकार में मंजूर हुए थे'' तथा उन्होंने अन्य मुद्दों का लेकर भी 'इनेलो – भाजपा' सरकार की आलोचना की।[8]

इसके अतिरिक्त व्यापारी वर्ग के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने हरियाणा में 'इनेलो – भाजपा' गठबन्धन सरकार की कार्यशैली की आलोचना की। इन्होंनेभाजपा की, जो व्यापारी वर्ग की पार्टी थी, की घोरनिन्दा की तथा इनेलों कोव्यापारी वर्ग का दुश्मन बताया। इन्होंने इनेलोसुप्रीमों चौ. ओम प्रकाशचौटाला के शासन को तानाशाही शासन बताया।[9] हरियाणा में सी. पी. आई(एम.) के नेताओं ने भी अनेकों बार इस गठबन्धन सरकार की आलोचना। सी.पी.आई (एम.) के नेताओं ने 10 अक्टूबर, 2004 का अपने राज्य सम्मेलन में 'इनेलो – भाजपा' गठबन्धन सरकार के चार साल का ब्यौरा दिया। इन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा में पिछले चार साल के अरसे में चौटाला की सरकार, जिसमें भारतीय जनत पाटी का बहार से समर्थन रहा, केन्द्र की जनविरोधी नीतियों को राज्य में लागू करती रही। प्रदेश में मुख्यमंत्री औम प्रकाश चौटाला व उसके दो बेटे दरबार सजाते, जिसमें तमाम नौकरशाही तथा मुफ्त खौर जी – हजूरी में लगे रहते। इस सरकार द्वारा घोषित 45000 विकास कार्य सरकारी कोष में घपलों को ही चिन्हित करते हैं। इस गठबन्धन सरकार के दौरान पचायतों में ग्राम विकास कमेटियां जोड़कर उन्हे पंगू बना दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था में गैर कानूनी संशोधन किया गया। इनेलो द्वारा एस.वाई.एल मुद्दे पर जनता को भ्रमित किया गया। सरकार का शासन निरंकुश मजदूर विरोधी,

© 2023 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: निधि
Submitted: 27JFeb 2023, Revised: 09 March 2023, Accepted: 18 March 2023, Published: April 2023

किसान विरोधी और कर्मचारी विरोधी रहा। निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा संस्थाओ को पंगू बनाकर मुख्यमंत्री व उसके दो राजकुमारों की अघोषित तानाशाही कायम रही ५ इस सरकार के कार्यकाल में किसान आन्दोलन को कुचलकर कंडेला में नो किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। किसान यूनियन के नेता घासीराम नैन पर राष्ट्रद्रोह का झुठा मुकद्दमा बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। 'इनेलो–भाजपा' के राज के चलते हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। में पाँच दलितों की दुलिना चौकी में निर्मम हत्या कर दी गई। हरसौला गाँव में गांव के दलितों को गांव से उजाड़ दिया गया तथा पहरावर दलित सरपंच कांड हुआ। इसमें जनता के भारी दबाव के चलते भी सरकार दोषियों केप्रशासन तथा पुलिस की हाजिरीपक्ष में खड़ी प्रतीत हुई। प्रदेश में शादी विवाह तोड़ने वाली गोत्र व जाति के नाम से गैर संवैधानिक पंचायतों व खापों को अपने मन माने ढंग से न्यायपालिका के समान्तर फतवे जारी करने की छुट दी गई। इस गठबन्धन सरकार के दौरान राज्य में लूट, डकैती दलितों पर अत्याचार व बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ी। इस गठबन्धन ने चुनावी मुद्दों में 70 हजार कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की थी। परन्तु इसकी अपेक्षा झूठी घोषणाओं के चलते 20 हजार कर्मचारियों को सरकार में घर भेज दिया। जिनमें चार हजार कर्मचारी अकेले एम.आई.टी.सी. विभाग से थे। प्रदेश में इस गठबन्धन सरकार ने कर्जा वसूली के दौरान बड़े पैमाने पर किसानों को जेल में बंद किया और किसानों की जमीनों को कुर्किया किया।[10]

हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही में कांग्रेस के नेता कैप्टनअजय सिंह यादव ने चौटाला सरकार पर आरोप लगाया कि, "गुड़गांव में 18 एकड़ भूमि फाइवस्टार होटल बनाने के लिए ये सरदार प्रकाश सिंह बादल को दे सकते हैं, लेकिन उनसे एस.वाई.एल. नहर के बारे में बात नहीं कर सकते।"[11]1941 कांग्रेस (आई) के अन्य नेताओं द्वारा भी इस गठबन्धन सरकार की आलोचना की गई।

इन आरोपों के बावजूद भी 'इनेलो – भाजपा' गठबन्धन सरकार ने हरियाणा में अनेक उपलब्धियां हासिल। यह गठबन्धन सरकार जनवरी, 2004 तक कार्य करती रही।

© 2023 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: निधि
Submitted: 27JFeb 2023, Revised: 09 March 2023, Accepted: 18 March 2023, Published: April 2023

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

[1]गुप्ता, एस.पी., थ्री डिकैडस ऑफ हरियाणा : ए डिस्क्रिपटिव स्टडी, ईसेस्पी पब्लिकेशन, चण्डीगढ, 1991
[2]गोयल, ओ.पी., कॉस्ट एण्ड वोटिंग बिहैवियर, रितु पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली, 1981
[3]चक्रवर्ती, बिद्युत, फॉरगोइंग पॉवर : कोईलिशन पोलिटिक्स इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, न्यू दिल्ली, 2006
[4]चन्द्र, एन.जे., कोईलिशन पोलिटिक्स : दी इंडियन एक्सपिरियंस, पब्लिसिंग कम्पनी, न्यू दिल्ली, 2004
[5]ढाका, रणबीर और ढाका, सुभिता, जननायक का सफरनामा, स्पैल बाऊंड पब्लिकेशन, रोहतक, 2001
[6]फडिया, बाबूलाल, स्टेट पोलिटिक्स इन इंडिया, रेडियट पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली, 1984
[7]मित्तल, एस.सी. हरियाणा : ए हिस्टोरिकल प्रैस्पक्टिव, अटलांटिक पब्लिशर्स, बिपज, 1984
[8]मुस्कैटा, ब्रुश बूनो डी., स्ट्रटजी, रिस्क, पर्सनलिटी इन कोईलिशन पोलिटिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 1975
[9]सिन्हा, सच्चीदानंद, कोईलिशन इन पोलिटिक्स, उपवल प्रैस, मुजफ्फरनगर, 1997
[10]अग्रवाल, पुरुषोत्तम, भाजपा के लिए खतरे की घंटी'', राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, 9 मार्च, 2000
[11]यादव, के.सी., दी रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा, मनोहर पब्लिकेशन, दिल्ली, 1977

© 2023 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: निधि
Submitted: 27JFeb 2023, Revised: 09 March 2023, Accepted: 18 March 2023, Published: April 2023